COOPERATION (SHRI D. ERING): (a) and (b). A scheme of Pilot Research Project in Growth Centres has been approved by the Planning Commission to be taken up during the Fourth Plan. The scheme seeks to identify potential growth centres as also viable rural communities around them in a few selected areas, and envisages, in this connection, setting up of twenty 'Research and Investigation Cells' in the select areas to undertake survey, collection and study of all relevant data with a view to identifying potential growth centres and a scheme of delineation of associate villages around them and prepare a 'Plan of development' as would enable the centres to pick up viability and tap the full development potential over a period of time. Thus the main objective of the Project is to study the factors and proceses involved in coordinated area development around emerging growth centres.

(c) The scheme is a centrally sponsored one and the entire expenditure would be met by the Centrel. Decision in regard to the location of Project Cells is being taken in consultation with the State Governments.

Supply of Treated Seeds to Farmers

2623. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to a survey conducted by the Planning Commission, it has been found that the supply of treated seeds even though has increased yet its increase is not sufficient to keep up the tempo of agricultural production in the country;

(b) if so, what particular steps are being taken to ensure adequate supply of treated seeds to the farmers; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Working of the Employees Provident Fund Organisation

2624. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the recommendations of the Administrative Reforms Commission on the working of the Employees Provident Fund Organisation involving policy matters; and

(b) if so, the details thereon ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) and (b). The administration of the Employees, Provident Fund is the concern of Central Board of Trustees. The Provident Fund authorities have reported that certain recommendations of the Administrative Reforms Department of the Home Ministry involving policy matters have been accepted recently by the Board of Trustees. They have not yet been referred to Government for approval. The Administrative Reforms Commission have not made any recommendation in regard to working of the Employees, Provident Fund Organisation.

Strike Notice by Sugar Industry Workers' Representatives

2625. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of LABOUR AND REHAUBILITATION be pleased to state :

(a) whether representativ of the workers in the Sugar Industry have issued a call to go on strike on the 23rd February, 1970 in support of their demand for wage revision and nationalisation of industries; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) Yes. A strike call was reported to have been issued.

(b) The question of wage revision has already been considered by the 2nd Sugar Wage Board and its recommendations are

now before the Government. The demand for nationalisation has been brought to the notice of the concerned Department.

पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव के बाद घेराव की घटनायें

2626. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव के बाद घेराव की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार इसके परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के उद्योगों को अनुमानतः कितनी हानि हुई है, और

(ग) घेराव के कारण पश्चिम बंगाल में कितने उद्योग बंद हो गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी. संजीवैया): (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जनवरी, 1970 के अन्त तक घेराओं की संख्या 539 थी। तीन औद्योगिक इकाईयां अस्थाई रूप से बंद हुईं, परन्तु बाद में पुनः चालू हो गईं। उद्योगों को हुई अनुमानित हानि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

गांवों में सरकारी गोदामों की स्थापना

2627. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीणों के लाभार्थ उन बड़े-बड़े गांवों में नगरों जैसे ही सरकारी गोदाम स्थापित करने की किसी परियोजना पर विचार करेगी जहां किसानों को निर्धारित मूल्यों पर आवश्यक सामान मिल सके;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एरिंग) : (क) से (ग). चौथी योजनावधि में ग्राम सेवा समितियों और विपणन समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोज्य वस्तुओं के वितरण की योजना राज्य योजना स्कीमों की अंग है, जिसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा कोई अलग योजना का प्रस्ताव नहीं है।

चौथी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में पम्पों का लगाया जाना

2628. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कितने पम्प लगाये जाने की सम्भावना है तथा कुल कितने गांव उठाऊ सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, मध्य प्रदेश में 33,000 सिंचाई पम्पसेट 4 नलकूपों को ऊर्जा देने का लक्ष्य राज्य योजना परिव्यय में निर्धारित किया गया है। फिर भी, संस्थानात्मक संसाधनों आदि से उपलब्ध अतिरिक्त धन की सहायता से अतिरिक्त पम्पसेटों 4 नलकूपों को ऊर्जा देने की आशा की जाती है।

मध्य प्रदेश में नल-कूप

2629. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :